



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 6, June 2023

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

कोरोना का भारतीय बैंकिंग अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Omprakash Meena

Assistant Professor in EAFM, S.P.N.K.S. Government College, Dausa, Rajasthan, India

सार

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से मची तबाही ने दुनिया की पूरी आर्थिक स्थिति को चरमरा दिया। शायद इतिहास का सबसे दुखद दौर मानव ने कभी देखा हो। चाहे वह विकासशील देश हो, अविकसित देश हो या दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो, कोई भी देश इसके दंश से सुरक्षित नहीं बच पाया। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बेहद प्रभावित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक; भारत के शीर्ष बैंक ने COVID19 महामारी का सामना करने के लिए अपनी नीति में विशेषज्ञों की मदद से आवश्यक बदलाव किए। पूरे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि तरलता का मुद्दा, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईपीओ दर में कमी की है। चूँकि लोग आय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाकर ग्राहक से ईएमआई भुगतान में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया। शोध पत्र का उद्देश्य आरबीआई द्वारा अपनी नीति में सीओवीआईडी -19 के कारण किए गए परिवर्तनों का अध्ययन करना है और सामान्य तौर पर यह भी अध्ययन करना है कि सीओवीआईडी -19 ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए COVID19 महामारी के कारण होने वाले नुकसान से निपटने के लिए समाधान प्रस्तावित है। शोध में पाया गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने बैंकिंग प्रणाली को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न उपाय जोड़े हैं। अधिकांश भारतीय बैंक एनपीए, ऋण की वसूली न होने, ग्राहक धोखाधड़ी, खराब ऋण आदि की समस्या का सामना कर रहे थे और इसके अलावा, सीओवीआईडी -19 ने भारतीय बैंकिंग व्यवसाय के पतन को तेज कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में बैंकों की स्थापना ग्राहकों को अपेक्षित सुविधा देकर लाभ कमाने के मूल उद्देश्य से की गई है। लेकिन Covid19 ने भारतीय ग्राहकों का परिदृश्य बदल दिया है। कारोबार बंद होने से लोगों की आय का जरिया ठप हो गया। तो फिर ऋण लेने और ब्याज सहित चुकाने की गुंजाइश कहां है। वर्तमान महामारी की स्थिति में हमारे भारतीय बैंक इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

परिचय

आर्थिक रूप से, दुनिया भर में COVID-19 का प्रकोप विनाशकारी था और इसने वित्तीय क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। महामारी ने विशेष रूप से बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए कई विशिष्ट समस्याएं पैदा कीं। विकासशील देशों में इसके अधिक गंभीर होने की संभावना है, जिनके पास अक्सर अपने वित्तीय बाजारों के लिए कम विकसित बुनियादी ढांचा होता है[1]। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, वित्तीय क्षेत्र अपनी नवीन क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकता है यह मुद्दा अनसुलझा है। बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।

बैंक एक वित्तीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले उद्यमों, सरकारों और अन्य संस्थाओं को ऋण देना है। जब पैसे की बात आती है, तो दुनिया भर के लोगों को बैंकों पर भरोसा होता है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सहित कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है। ये सेवाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एनबीएफसी को अधिक धन उधार देने, आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने और अन्य समान गतिविधियों के माध्यम से मांग बढ़ाने और तरलता कम करने के बैंक के प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रदान की जाती हैं।[1,2]

बैंक भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है और देश में नौकरियाँ पैदा करने में मदद करता है। सरकारी बैंकों की हालत पहले से भी बदतर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुरोध किया है कि देश के सभी बैंकिंग संस्थान नए कोरोना वायरस समस्या के मद्देनजर सिस्टम में तरलता लाने के लिए ईएमआई भुगतान पर तीन महीने की रोक लगाएँ।[1] उनके वित्तीय रिकॉर्ड में उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपायों को दर्शाया जाएगा।

बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), अवैतनिक ऋण और ऋण आवश्यकताएँ प्रमुख योगदानकर्ता थीं। और परिणामस्वरूप, 2019 की शुरुआत में बैंकों का मुनाफा कम हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने भारतीय वित्तीय संस्थानों पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए संघीय और राज्य स्तर पर कई उपाय किए। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, महामारी की गंभीरता के आधार पर, विशेष रूप से भारत में बैंकिंग उद्योग को ठीक होने में काफी समय लग सकता है।



कोविड-19 के प्रभाव क्षेत्र

समस्या के मूल में जाने से पहले आइए भारतीय बैंकिंग उद्योग पर कुछ संदर्भ प्रदान करके शुरुआत करें। जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है, चाहे कितना भी पैसा जमा कर रहा हो, व्यक्ति समझता है कि बैंक में पैसा किसी भी स्थान की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा, बैंक कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें ऋण और जमा के विकल्प, सावधि जमा कार्यक्रम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सेवाएँ और बहुत कुछ शामिल हैं।

भारत में अब 33 बैंक कार्यरत हैं, जिनमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और 21 निजी हैं। बैंकिंग उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कई नौकरियाँ प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के बैंकों के कई प्रमुख प्रदर्शन उपायों में लगातार गिरावट आई है[2]।

कोरोनावायरस: भारत पर COVID-19 का आर्थिक प्रभाव - राबो रिसर्च

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं[1]:

रेपो रेट- आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई, जिससे यह 4.4 पर आ गई। इस साल अक्टूबर से पहले रेपो रेट 5.15 फीसदी थी।

रिवर्स रेपो- मौद्रिक प्राधिकरण ने यह भी घोषणा की कि वह रिवर्स रेपो दर में 90 आधार अंक या 0.90% की कमी करेगा। हर दिन औसतन 3 लाख करोड़ रुपये बैंक आरबीआई के पास जमा करते रहे हैं। फिलहाल, रिवर्स रेपो रेट 4 फीसदी था।

ऋण अधिस्थगन- आरबीआई गवर्नर ने 1 मार्च 2020 को देय सावधि ऋणों पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया। यह क्षेत्रीय, ग्रामीण, लघु वित्त, सहकारी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। गृह वित्तपोषण और माइक्रोफाइनेंस।

सीआरआर-नकद आरक्षित अनुपात को 4% से घटाकर 3% किया जाएगा, जैसा कि आरबीआई ने संकेत दिया है। 23 मार्च से शुरू होकर, इससे अर्थव्यवस्था में लगभग 137,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे।

एलटीआरओ- आरबीआई दीर्घकालिक रेपो परिचालन भी करेगा, जिससे बैंकों को अधिक नकदी मिलेगी। बैंकों को इस तरलता को वाणिज्यिक पत्रों, निवेश-ग्रेड बांड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश करना चाहिए।

कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में आसानी- ऋणदाता उधारकर्ता के कार्यशील पूंजी चक्र का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और ड्राइंग पावर की पुनर्गणना करने के लिए मार्जिन को समायोजित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई से परिसंपत्तियों का अवमूल्यन नहीं होगा।

एमएसएफ- एसएलआर का प्रतिशत जिसे त्रुटि के लिए मार्जिन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, और यह 30 जून, 2020 तक उस स्तर पर रहेगा। संकट की अवधि में, बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त 137,000 तक पहुंचने में सक्षम होगी। आरबीआई के अनुसार, एलएएफ विंडो के माध्यम से रियायती दर पर करोड़ रुपये की तरलता।

ताज़ा तरलता-गवर्नर के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, सभी घोषणाओं का सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3.2% के बराबर प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार, फरवरी 2020 से देश को तरलता इंजेक्शन में कुल 2.8 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 1.4% प्राप्त हुआ है।[3,5]

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2020 की दूसरी तिमाही में 24% की गिरावट आई, जो कि कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक गिरावट है, जो कोविड-19 के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित थे। इसका कोई सबूत नहीं है कि केंद्र सरकार के आश्वासन के विपरीत, वी-आकार की रिकवरी होगी। सरकार की पिछड़ी और गलत नीति प्रतिक्रिया ने नुकसान की गंभीरता में योगदान दिया। "केंद्र सरकार का अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक प्रतिशत था[2]।"

परिणामस्वरूप, अपनी नौकरी और आजीविका खो चुके कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मदद करने के सरकार के प्रयास दुखद रूप से अपर्याप्त रहे हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है और और भी अधिक लोगों के लिए जीवन कठिन हो गया है। इसकी वजह से, वायरस के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में तत्काल रोक और उस पर लॉकडाउन प्रतिक्रिया से आपूर्ति पक्ष को झटका



लगा है, जो गंभीर मांग संपीड़न से प्रभावित हुआ है। भारत सरकार पहले से ही मौद्रिक साधनों की ओर झुक रही थी क्योंकि उसने कोविड-19 संकट आने से पहले ही नवउदारवाद को स्वीकार कर लिया था।

विचार-विमर्श

अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए, नीति निर्माताओं ने तरलता इंजेक्शन मौद्रिक प्रोत्साहन का सहारा लिया है। उस क्रेडिट की आपूर्ति से जुड़ा जोखिम बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वहन किया जाना है, क्रेडिट प्रवाह के एक सीमित अंश को छोड़कर, तरलता इंजेक्शन का निर्माण करने का इरादा था, जिसकी आंशिक या पूर्ण गारंटी सरकार द्वारा दी गई थी।

डिफॉल्ट के प्रभाव को कम करने के लिए, केंद्रीय बैंक ने दिसंबर 2020 तक सभी उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम और ऋण सेवा भुगतान पर रोक लगाने की अनुमति दी है। कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में बैंक ऋण की बढ़ती मांग के कारण व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तपोषण के असुरक्षित रूपों में कमी।

कुछ भारतीय बैंकों को अपनी जमा राशि पर COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण अपना ऋण चुकाने में परेशानी हो रही है। कोरोना के परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा दी गई 3 महीने की छूट अवधि के बावजूद बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बढ़ गई हैं, जिससे खराब क्रेडिट मान्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों का बोझ कम हो गया है। बैंकर्स जानते हैं कि 25 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के बाद से आरबीआई ने बैंकिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश भुगतान को निलंबित करने के अलावा, आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप खराब क्रेडिट वाले देनदारों के लिए अनुग्रह अवधि बढ़ा दी है। लॉकडाउन ने बैंकों की हालत खराब कर दी है। अब लॉकडाउन हटा दिए जाने के बाद सब कुछ सामान्य होने में अधिक समय लगेगा।[7,8]

दूसरी ओर, सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ और भी अधिक बढ़ सकती हैं। इससे इस दावे को विश्वसनीयता मिलेगी कि भारत सरकार के पास इन बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए आवश्यक धन की कमी है, जिससे आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए निजी निवेशकों को शेयरों की बिक्री की आवश्यकता होती है। अधिकांश स्थितियों में, इसका अर्थ अधिकतर सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली का अंत होगा।

सुझाव

कोविड-19 के मामले में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई को अब बैंकिंग प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लॉकडाउन हटने के बाद सभी छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण तक पहुंच की आवश्यकता होगी, और यह सेवा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। लॉकडाउन हटने के बाद सभी छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण तक पहुंच की आवश्यकता होगी, और यह सेवा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। धन और पूंजी बाजार का सुचारु रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार को आर्थिक तनाव और चिंता को कम करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर रहे कि आने वाली महामारी से बचा जा सके, दूसरी ओर, सार्वजनिक बैंकों के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में भारत सरकार को महामारी के दौरान सीधे नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस पर सरकार ने प्रस्ताव रखा "बैंक बिक्री विधेयक" (निजीकरण) के पारित होने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा और सरकार को उसकी देनदारियों से राहत मिलेगी। मेरी राय में, सार्वजनिक बैंकों का धीरे-धीरे निजीकरण किया जाना चाहिए, और इससे सरकार को अन्य प्रभावशाली कारकों जैसे मांग/आपूर्ति, नीतियां, मुद्रास्फीति और बैंकिंग क्षेत्र को निजी संगठनों पर छोड़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।

परिणाम

भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:

भारत-चीन व्यापार संबंध:

- भारत अपने कुल आयातित माल का 18%, इलेक्ट्रॉनिक घटक का 67% एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का 45% चीन से आयात करता है।

India-China trade in calendar 2019

Imports from China **86.2**Exports to China **29.5**

Indian exports to China

Gems and jewellery

36%

Mineral and ores

15%

Organic chemicals

11%

India's Imports from China

Electrical machinery

34%

Nuclear reactors and machinery

18%

Organic chemicals

10%

- भारत जब अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में इस वायरस का केवल सतही प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसे कठिन समय में समस्या का समाधान मात्र 'एयर लिफ्टिंग' से संभव नहीं है।
- यह समस्या न केवल आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगी, अपितु यह भारत के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।
- निर्यात, जिसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन माना जाता है, इसमें वैश्विक मंदी की स्थिति में और गिरावट देखी जा सकती है, साथ ही निवेश में भी गिरावट आ सकती है।
- सकारात्मक पक्ष:
- भारतीय कंपनियाँ चीन आधारित 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला' में शामिल प्रमुख भागीदार नहीं हैं, अतः भारतीय कंपनियाँ इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगी।
- दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, जो कि वृहद् अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रास्फीति के चलते अच्छी खबर है।^[5,7]
- सामान्य वित्तीय संकट से अलग:
- वायरस जनित यह संकट किसी अन्य वित्तीय संकट से बिलकुल अलग है। अन्य वित्तीय संकटों का समाधान समय-परीक्षणित उपायों (Time-tested Measures) जैसे- दर में कटौती, बेल-आउट पैकेज (विशेष वित्तीय प्रोत्साहन) आदि से किया जा सकता है, परंतु वायरस जनित संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।
- भारत सरकार को लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है, साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की जानी चाहिये ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

निष्कर्ष

दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और तेजी से पूरी दुनिया में फैलने वाला COVID-19 का प्रकोप धीरे-धीरे कम होने के संकेत दे रहा है। मार्च 2022 के मध्य में, महामारी के दो साल से अधिक समय के साथ, वायरस 200 से अधिक न्यायक्षेत्रों में फैल गया है और 460 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और छह मिलियन से अधिक मौतें हुई हैं (डेटा 2022 में हमारी दुनिया)। वैश्विक आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यवधान के अलावा, आउटलुक ने एक बड़ी आर्थिक मंदी उत्पन्न की, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई।

तीव्र और अचानक मंदी (कैवेलिनो और डी फियोर 2020) के अप्रिय प्रभावों को रोकने के लिए देशों ने निर्णायक और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी। एक ओर, सरकारों ने केंद्रीय बैंकों (आईएमएफ 2020बी) द्वारा आपातकालीन सहायता उपायों के अलावा बड़े पैमाने



पर राजकोषीय प्रोत्साहन (आईएमएफ 2020ए) लॉन्च किया। इसके अलावा, विवेकपूर्ण नीतियों ने ऋण वृद्धि (बीआईएस 2020ए) सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों का समर्थन किया। साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने और समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने के उपाय भी किए गए। जनवरी 2020 से शुरू होकर जून 2021 तक की 18 महीने की अवधि के लिए, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कुल मौद्रिक और राजकोषीय खर्च 16.5 बिलियन डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (आईएमएफ 2021) का लगभग 16% था। [8]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

- 1) अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय - ईटी बीएफएसआई। ETBFSI.com. (2020)। 17 सितंबर 2022 को <
- 2) <https://bfsi.आर्थिकtimes.indiatimes.com/news/policy/10-decisions-taken-by-rbi-to-counter-coronavirus-impact-on-economy/74844644> > से लिया गया।
- 3) केंगे, आर., और खान, ज़ेड. (2020)। मंदी, इसका प्रभाव और भारत की प्रतिक्रिया। 26 सितंबर 2022 को < <https://www.jstor.org/stable/48590645> > से लिया गया
- 4) कानितकर, टी. (2021)। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव: एक आलोचनात्मक विश्लेषण। 26 सितंबर 2022 को < <https://www.jstor.org/stable/26965501> > से लिया गया
- 5) कोविड-19: बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव। (2020)। 26 सितंबर 2022 को <
- 6) <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/07/covid-19-impact-on-banking-m-and-a-2020.html> > से लिया गया
- 7) कौजियानौ, पी., और रीड, टी. (2020)। उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव: एक आशावादी प्रारंभिक लेखा-जोखा। 26 सितंबर 2022 को <
- 8) <https://www.jstor.org/stable/26996640> > से लिया गया



Impact Factor: 8.423



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details